स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024

हाल ही में हुए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश के तीन शहर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहरो में शामिल हुए।

प्रमुख बिंदु

- **कुल मूल्यांकित शहर: 131**
- **देश में शीर्ष स्थान:** सूरत ने 131 अन्य शहरों को पीछे छोड़ते हुए आयोजित 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024' में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
- **यूपी के शहर सूचीबद्ध:** वायु प्रदूषण कम करने के प्रयासों के लिए आगरा को श्रेणी 1 (10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर) में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ।
  - फिरोजाबाद और रायबरेली को श्रेणी II और III (क्रमशः 3 से 10 लाख के बीच और 10 लाख से कम आबादी वाले शहर) में प्रथम स्थान दिया गया।
- विजेताओं को 7 सितंबर को जयपुर, राजस्थान में स्वच्छ वायु दिवस पर आधिकारिक रूप से सम्मानित किया जाएगा।

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के बारे में

- **सम्मिलित मंत्रालय:** यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है।
- **लॉन्च किया गया:** इसे 2019 में लॉन्च किया गया था।
- **मूल्यांकन पैरामीटर:** यह शहरों द्वारा वायु गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों का मूल्यांकन करता है, जिसका लक्ष्य पार्टिकुलेट मैटर को कम करना है। शहरों का मूल्यांकन आठ मापदंडों पर किया जाता है, जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क धूल नियंत्रण, निर्माण अपशिष्ट, वाहनों से होने वाला उत्सर्जन, औद्योगिक उत्सर्जन, जागरूकता कार्यक्रम और समग्र वायु गुणवत्ता में सुधार।
- **कार्यान्वयन:** पिछले पांच सालों में, एसएमसी ने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को लागू किया है। इन परियोजनाओं में मैकेनिकल स्वीपर के माध्यम से सालाना 4,200 मीट्रिक टन धूल हटाना, कचरा संग्रह बेड़े में 35% इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करना, जिसके परिणामस्वरूप सालाना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 7,000 मीट्रिक टन की कमी आई है और 50 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन और बुनियादी ढांचा प्रदान करना शामिल है।

सविल्स इंडिया की सस्टेनेबल रियल एस्टेट पर रिपोर्ट

हरित रियल एस्टेट परियोजनाओं की सूची में महाराष्ट्र शीर्ष पर, एवं उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा।

रिपोर्ट के बारे में

- **सविल्स इंडिया की सस्टेनेबल रियल एस्टेट रिपोर्ट:** स्ट्रैटेजीज एंड प्रैक्टिसेज पर रिपोर्ट में कहा गया है कि शीर्ष 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 7000 से अधिक आईजीबीसी-ग्रीन प्रमाणित परियोजनाएं हैं।
- रिपोर्ट में महत्वपूर्ण रणनीतियों और नवीन दृष्टिकोणों को रेखांकित किया गया है जो 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के राष्ट्र के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के बीच भारत में टिकाऊ रियल एस्टेट विकास के लिए नए मानक स्थापित कर रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- सविल्स इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, टिकाऊ इमारतों के लिए प्रोत्साहन देने की अपनी नीति के कारण महाराष्ट्र देश भर में हरित रियल एस्टेट परियोजनाओं (1094 परियोजनाएं) की सूची में शीर्ष पर है।

- **उत्तर प्रदेश 643 परियोजनाओं के साथ दूसरे स्थान पर रहा और गुजरात 590 परियोजनाओं के साथ तीसरे स्थान पर** रहा। कुल दस लाख वर्ग फीट जगह के मामले में महाराष्ट्र और तेलंगाना सबसे आगे हैं।
- हरित परियोजनाओं की कुल संख्या के संदर्भ में, तेलंगाना 519 परियोजनाओं के साथ चौथे स्थान पर है, कर्नाटक 501 परियोजनाओं के साथ पांचवें स्थान पर है, तमिलनाडु 495 हरित परियोजनाओं के साथ छठे स्थान पर है और हरियाणा 450 परियोजनाओं के साथ सातवें स्थान पर है।
- रिपोर्ट के अनुसार, 242 हरित परियोजनाओं के साथ दिल्ली 14वें स्थान पर है।
- **क्लस्टर वर्गीकरण:** रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र और तेलंगाना शीर्ष रैंक वाले आकार वाले समूह बनाते हैं, जहां औसत परियोजनाएं 0.36 - 0.37 मिलियन वर्ग फुट हैं, जबकि कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु को दूसरे समूह में रखा जा सकता है जहां परियोजनाएं 0.25 - 0.27 मिलियन वर्ग फुट की सीमा में हैं।
  - उत्तर प्रदेश और दिल्ली तीसरे समूह का निर्माण करते हैं, जिनकी परियोजना का आकार 0.18 मिलियन वर्ग फुट है। पश्चिम बंगाल और हरियाणा चौथे समूह का निर्माण करते हैं, जिनकी परियोजना का आकार 0.12-0.14 के बीच है।

यूपी विशिष्ट विवरण

- उत्तर प्रदेश ने, अपने तीव्र शहरीकरण के साथ, ऐसी नीतियां भी लागू की हैं जो आईजीबीसी से हरित रेटिंग प्राप्त करने वाले होटल/वेलनेस रिसॉर्ट्स को आईजीबीसी प्रमाणन शुल्क के 50% की प्रतिपूर्ति, अधिकतम 10 लाख रुपये तक, जैसे विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से हरित भवन को प्रोत्साहित करती हैं।
- सरकार उन परियोजनाओं के लिए 10% एफएआर भी प्रदान करती है जो आईजीबीसी द्वारा गोल्ड या उससे ऊपर के रूप में पूर्व-प्रमाणित/अस्थायी रूप से प्रमाणित हैं।
- इसमें कहा गया है कि ये प्रोत्साहन ग्रीन बिल्डिंग प्रथाओं को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे इन राज्यों को सतत विकास में आगे बढ़ने में मदद मिलती है।

आगे का मार्ग

- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में, भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहा है। रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विकास के हर चरण में टिकाऊ सामग्रियों और ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
- जैसे-जैसे भारत अपने जलवायु लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है, सभी क्षेत्रों की कंपनियां तेजी से संधारणीय प्रथाओं को अपना रही हैं। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला रियल एस्टेट उद्योग इन परिवर्तनों को अपना रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कॉर्पोरेट और परिसंपत्ति-स्तरीय पहल दोनों ही देश की जलवायु महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप हों। यह सामूहिक प्रयास एक लचीले और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय भविष्य की दिशा में प्रगति को आगे बढ़ा रहा है।

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) लखनऊ के एंटरप्राइज इनक्यूबेशन सेंटर ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई-बीटी) की शुरुआत की है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनी स्टार्ट-इन-अप नीति के तहत समर्थित एक पहल है।

प्रमुख बिंदु

- **आउटरीच केंद्र:** सीओई-बीटी पहल के अनुरूप, एंटरप्राइज इनक्यूबेशन सेंटर ब्लॉकचेन-आधारित नवाचार को बढ़ावा देने और पोषित करने के लिए उत्तर प्रदेश में तीन आउटरीच केंद्र स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ साझेदारी करेगा।
  - प्रस्तावित केंद्र गोरखपुर, लखनऊ और ग्रेटर नोएडा/मेरठ में स्थित होंगे।
- **स्टार्टअप:**नई सुविधा का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में ब्लॉकचेन क्षेत्र में 100 स्टार्टअप का सृजन और पोषण करना है, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा।
- आईआईएम लखनऊ के अनुसार यह पहल विभिन्न क्षेत्रों में विश्वास, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करके ई-गवर्नेंस को बढ़ाने के राज्य सरकार के उद्देश्य के अनुरूप है।

एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री ने हाल ही में पूसा, नई दिल्ली में एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किया।

स्टार्ट-अप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष (एग्रीश्योर) के बारे में:

- क्षेत्र-विशिष्ट, क्षेत्र-विशिष्ट और ऋण वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में निवेश के माध्यम से स्टार्ट-अप और कृषि उद्यमियों को समर्थन देना, साथ ही कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप को प्रत्यक्ष इक्विटी समर्थन देना।
- **उद्देश्य**: 750 करोड़ रुपये की श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) की स्थापना के माध्यम से भारत के कृषि क्षेत्र में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देना।
  - यह फंड इक्विटी और ऋण दोनों प्रकार की सहायता प्रदान करेगा, विशेष रूप से कृषि मूल्य श्रृंखला में उच्च जोखिम, उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों को लक्षित करेगा।
- **मंत्रालय**: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
- नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नैबवेंचर्स (NABVENTURES), एग्रीश्योर के फंड मैनेजर के रूप में कार्य करेगी।

कृषि निवेश पोर्टल:

- **उद्देश्य**: देश में कृषि निवेश को बढ़ावा देना।
- विकसित: सभी कृषि निवेशकों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने हेतु एक एकीकृत, केंद्रीकृत वन-स्टॉप पोर्टल के रूप में विकसित किया गया है।

ऑपरेशन भेड़िया

उत्तर प्रदेश सरकार ने कई लोगों की जान लेने वाले भेड़ियों के झुंड को पकड़ने के लिए 'ऑपरेशन भेड़िया' शुरू किया है।

प्रमुख बिंदु

- **ऑपरेशन का उद्देश्य:** उत्तर प्रदेश के बहराइच में बच्चों और ग्रामीणों को निशाना बना रहे भेड़ियों को पकड़ने के लिए।
- वन विभाग इन शिकारियों को पकड़ने के लिए **झूठे चारे के रूप में बच्चों के मूत्र में भिगोए गए "टेडी डॉल्स" का उपयोग** कर रहा है।

इंडियन वुल्फ (कैनिस ल्यूपस पल्लिप्स) के बारे में:

- विवरण: आकार में मध्यम, तिब्बती और अरब भेड़ियों के बीच स्थित।
- यह झाड़ियों, घास के मैदानों और अर्ध-शुष्क देहाती कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र वाले क्षेत्रों में पाया जाता है।
- यह भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर इजराइल तक व्यापक रूप से वितरित है।
- **संरक्षण स्थिति:**
  - आईयूसीएन: कम से कम चिंता का विषय
  - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972: अनुसूची I
  - उद्धरण: परिशिष्ट 1

वैदिक-3डी संग्रहालय

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने काशी स्थित सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में भारतीय ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान तथा वैदिक साहित्य को समर्पित वैदिक-3डी संग्रहालय के निर्माण का आदेश दिया है।

प्रमुख बिंदु

- संग्रहालय में वैदिक साहित्य के विकास को दर्शाया जाएगा, जिसमें **16 संस्कार, 64 कलाएं और 18 विद्या स्थलों पर प्रकाश** डाला जाएगा।
- संग्रहालय में ऐतिहासिक सरस्वती भवन में संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियाँ प्रदर्शित की जाएँगी, जैसे कि **"रास पंचाध्यायी", श्रीमद् भागवत गीता और दुर्गा सप्तशती,** सभी पर जटिल रूप से उत्कीर्ण और स्वर्ण कलाकृति से सुसज्जित हैं। इसका उद्देश्य 'शास्त्रार्थ' (आध्यात्मिक प्रवचन) की परंपरा को पुनर्जीवित करना और वैदिक साहित्य में ज्ञान को गहरा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना है।

भारत का 23वाँ विधि आयोग

भारत के राष्ट्रपति ने 23 वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसका कार्यकाल **1 सितंबर, 2024 से 31 अगस्त, 2027 तक** निर्धारित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- **सदस्य:** आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, चार सदस्य और अतिरिक्त पदेन और अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे।
- आयोग का कार्य भारतीय कानूनी प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा करना और सुझाव देना है।
- 22वें विधि आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया। आयोग कई महीनों से बिना अध्यक्ष के काम कर रहा है, जिससे समान नागरिक संहिता और एक साथ चुनाव कराने जैसी महत्वपूर्ण रिपोर्टें आने में देरी हो रही है। मार्च 2024 में विधि आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी ने 17 महीने के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया था।

लघु समाचार

- उत्तर प्रदेश सरकार ने **जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए नियुक्त दोषी कंपनियों** के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है।

विविध

- सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अपनी बैठक में रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) से **26,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से रूसी मूल के एसयू-30 एमकेआई लड़ाकू विमान के लिए 240 एयरो-इंजन (एएल-31एफपी) की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी** दी।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के हालिया आंकड़ों के अनुसार, तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान वित्त वर्ष 24 में भारत के 10 सबसे बड़े राज्यों में आर्थिक विकास में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं।
  - सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी), एक महत्वपूर्ण मीट्रिक जो किसी राज्य के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है, इन राज्यों द्वारा हासिल किए गए मजबूत आर्थिक विस्तार पर प्रकाश डालता है।

❍❍❍❍